भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 3178

गुरूवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन कार्यनीतियाँ

3178 डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारण है कि व्यापक प्रबंधों के बावजूद प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की वर्तमान कार्यनीतियां विफल हो रही हैं;

(ख) क्या मंत्रालय भगदड़ में होने वाली मौतों की उच्च संख्या को देखते हुए, समारोहों के लिए एक समान सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्थलों के पारिस्थितिक संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए पर्यटकों के लिए अभिगम्यता संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार दैनिक आगंतुकों की संख्या सीमित करने जैसे उपाय शुरू करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटक स्थलों पर भीड़ और पर्यटकों के अंतर्वाह के प्रबंधन सहित पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना संबंधी मामले को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के समक्ष निरंतर उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

पर्यटन मंत्रालय की 'स्वदेश दर्शन', 'प्रशाद' और 'केंद्रीय एजेंसियों की सहायता' नामक योजनाओं द्वारा एक समावेशी, एकीकृत और स्थायी तरीके से अवसंरचना का विकास किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा, पहुंच और पारिस्थितिकीय परिरक्षण पर ध्यान दिया जाता है।

आगंतुकों की सुरक्षा और संरक्षा, पहुंच और पर्यावरणीय स्थिरता को बेहतर बनाने के उद्देश्य के साथ ही रैंप, रेलिंग, सीसीटीवी तंत्र, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, साइनेज, प्रकाश व्यवस्था, कतार परिसर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कई घटकों को मंजूरी दी गई है।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के दौरान, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऊपर निर्बाध पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतों, निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता देने और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन के विकल्पों को अपनाने के लिए जोर देता है। इसके अलावा, स्थायी संचालन और अनुरक्षण योजनाओं को शामिल करने पर जोर दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2014 में उनके द्वारा राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, प्रशासकों और आयोजकों को सामूहिक समारोहों तथा स्थलों पर भीड़ का प्रबंधन करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

*****